

Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of December, 2019.

During the month I took a meeting to review the implementation status of decisions taken by the Cabinet Committee on Security (CCS) regarding measures to be taken for Bodo Community in Assam.

2. Union Home Secretary chaired the 47th High Level Empowered Committee meeting on 26.12.2019 to review various border projects.
3. The entire state of Nagaland has been declared as "disturbed area" under Armed Forces Special Powers Act, 1958 for a period of six months from 30.12.2019 to 29.06.2020.
4. The Suspension of Operation (SoO) agreements signed with National Democratic Front of Bodoland (NDFB)/ Ranjan Daimary and NDFP/ Progressive of Assam have been extended for a further period of six months upto 30.06.2020.
5. The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 (Act No. 44 of 2019) has been notified on 09.12.2019. The provisions of the Act shall come into force on 26.01.2020.
6. Gazette notification regarding extension of the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Act, 2014 (Haryana Act No. 19 of 2015) to the UT of Chandigarh has been published in Gazette of India (Extraordinary) on 16.12.2019.
7. In compliance to the decisions of CoS, the Government Printing Presses, at Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli and Chandigarh have been closed. 02 nos. of Printing Press in Delhi Police and 05 nos. of Printing Press in Lakshadweep have been also closed.
8. NOC has been issued for changing the name of village "Amin" as "Abhimanyupur" in District Kurukshetra, Haryana.

9. CCTNS software has been deployed in 14973 Police Stations across the country. 14695 Police Stations are entering 100% FIRs through CCTNS. All States/ UTs have launched their State Citizen Centric Portals. CCTNS National Data Centre is getting data from 35 States/ UTs.

10. During the month, sanction for prosecution for filing the charge sheet against 43 accused persons was accorded in accordance with section 45(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sections 188 86 196 of CrPC.

11. During the month of December, 2019 an amount of Rs 21.047 crore has been released to the State Government of Sikkim under BADP. The total fund released under BADP during the Current financial year (2019-20) (as on 31.12.2019) is Rs 598.78 crore.

12. During the month Sub-Committee of National Executive Committee (SC-NEC) meeting was held to consider the report of inter-Ministerial Central Teams on Floods/Landslide/Cloudburst of 2019 in Assam, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and on unseasonal/heavy rains of October, 2019 in Maharashtra.

13. MHA has conducted an orientation workshop on 13th December, 2019 to sensitize States/ UTs officials for providing on line data through National Disaster Management Information System (NDMIS). 52 officials from 17 States/ UTs have participated in the workshop.

14. 180 officials of various States Police/CAPFs/CPOs have been awarded "ASADHARAN AASUCHANA KUSHALATA PADAK" for the year 2019, on 23rd December, 2019.

15. Sanction has been issued for creation of 899 posts in CISF.

16. Total Number of 250 Coys of CAPFs were deployed in various States Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh, Telangana, Assam, Manipur, Tripura, Meghalaya, Delhi, Puducherry, Karnataka, Gujarat for maintaining law and order duties.

17. An amount of Rs 36.55 Crore was released for execution of Swatchata Action Plan related works through CPWD during the years 2019-20 to 2020-21 at various locations of CRPF.

18. An amount of Rs 34.72 Crore has been sanctioned for development of infrastructure to the CAPF. An amount of Rs. 4.54 Crore has been sanctioned as Ex-gratia Compensation to the NOKs of CAPFs in 21 cases.

19. The Hon'ble President on 02.12.2019 has assented to the Tamil Nadu Acquisition Law (Revival of Operation and Validation) Bill, 2019.

20. Instructions of the Hon'ble President for promulgation of the Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Dr. Jayalalithaa Memorial Foundation Ordinance, 2019 have been conveyed to State Government on 20.12.2019.

21 The proposal for withdrawal of the Private Detective Agencies (Regulation) Bill 2007 has been approved by the Cabinet in its meeting held on 11-12-2019. Motion for withdrawal of the Bill, will be moved during the coming session of Parliament.

**दिसम्बर, 2019 के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, उल्लेखनीय
घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां**

इस माह के दौरान, मंत्री महोदय ने असम में बोडो समुदाय के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक ली।

2. केन्द्रीय गृह सचिव ने विभिन्न सीमा परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26.12.2019 को उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 47वीं बैठक की अध्यक्षता की।

3. संपूर्ण नागालैंड राज्य को दिनांक 30.12.2019 से 29.06.2020 तक छः महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, 1958 के अंतर्गत "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित किया गया है।

4. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)/रंजन दयामारी तथा एनडीएफपी/प्रोग्रेसिव, असम के साथ हस्ताक्षरित अभियान निलंबन करारों को दिनांक 30.06.2020 तक छः और महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

5. दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 44) को दिनांक 09.12.2019 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान दिनांक 26.01.2020 को लागू होंगे।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 (वर्ष 2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने से संबंधित राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.12.2019 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।

7. सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णयों के अनुपालन में, दमण और दीव, दादरा नगर हवेली तथा चंडीगढ़ में सरकारी मुद्रणालयों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के दो मुद्रणालयों तथा लक्षद्वीप के पांच मुद्रणालयों को भी बंद कर दिया गया है।

8. कुरुक्षेत्र जिला, हरियाणा में "अमीन" का नाम बदलकर "अभिमन्युपुर" करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

9. पूरे देश में 1497 पुलिस थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगाया गया है। 14695 पुलिस थानों में सीसीटीएनएस के माध्यम से शत-प्रतिशत प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्टेट सिटीजन सेंद्रिक पोर्टलों का शुभारंभ किया है। सीसीटीएनएस राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़ा प्राप्त हो रहा है।
10. इस माह के दौरान, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 86 196 के अनुसार, 43 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
11. दिसम्बर माह के दौरान, बीएडीपी के अंतर्गत सिविकम राज्य सरकार को 21.047 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत जारी कुल निधि (दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) 598.78 करोड़ रुपए है।
12. इस माह के दौरान, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में बाढ़ों/भू-स्खलन/बादल फटने/घटना तथा महाराष्ट्र में अक्टूबर, 2019 में बे-मौसम भारी बारिश के बारे में अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति की बैठक आयोजित की गई।
13. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) के माध्यम से ऑनलाइन डाटा प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को विषय परिचायन (ओरिएंटेशन) कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला में 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 52 अधिकारियों ने भाग लिया।
14. विभिन्न राज्यों की पुलिस/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के 180 अधिकारियों को वर्ष 2019 के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" प्रदान किया गया है।
15. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 899 पदों के सृजन हेतु स्वीकृति जारी की गई है।

16. विभिन्न राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, दिल्ली, पुडुचेरी, कर्नाटक, गुजरात में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की ऊ्यूटी के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 250 कंपनियों को तैनात किया गया।

17. वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न अवस्थानाओं पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से स्वच्छता कार्य योजना संबंधी कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए 36.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

18. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 34.72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 21 मामलों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निकट रिश्तेदारों को अनुग्रह मुआवजा के रूप में 4.54 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

19. माननीय राष्ट्रपति महोदय ने तमिलनाडु अधिग्रहण कानून (प्रचालन को दोबारा शुरू करना और उसका विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 को स्वीकृति प्रदान की है।

20. तमिलनाडु पुराची तैलवी डॉ. जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन अध्यादेश 2019 के प्रख्यापन हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश दिनांक 20.12.2019 को राज्य सरकार को संसूचित किए गए हैं।

21. मंत्रिमंडल ने दिनांक 11.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में निजी गुप्तचर एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007 को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। संसद के आगामी सत्र के दौरान, विधेयक को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा।
